भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4427
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य

4427. श्री मितेश पटेल (बकाभाई):
श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल:
श्री देवुसिंह चौहान:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस वार्ता का भारत द्वारा वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में क्या योगदान है;

(ख) यूनाइटेड किंगडम ग्रिड लचीलापन और ऊर्जा भंडारण समाधानों को सुदृढ़ करने में भारत की किस प्रकार सहायता करेगा;

(ग) इस वार्ता के अंर्तगत भारत के ऊर्जा संक्रमण में हरित हाइड्रोजन और अपतटीय पवन ऊर्जा क्या भूमिका निभाएंगे; और

(घ) ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए क्या प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष अथवा ज्ञान के आदान-प्रदान संबंधी पहलें प्रस्तावित हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : निवल-शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तकनीकी उपायों और वित्तीय उपायों सहित विभिन्न उपायों की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आयोजित संवाद, अन्य देशों के भागीदार संगठनों और वैश्विक संगठनों के बीच ज्ञान साझा करने के माध्यम से निवल-शून्य की दिशा में भारत के प्रयासों का समर्थन करता है। वर्ष 2023 में भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान, जी-20 नई दिल्ली अध्यक्षता घोषणापत्र जारी किया गया जिसमें निम्न-जीएचजी/निम्न-कार्बन उत्सर्जन को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई।

(ख) से (ग) : चौथी भारत-यूके मंत्रिस्तरीय ऊर्जा वार्ता, जिसकी सह-अध्यक्षता विद्युत मंत्री और यूनाइटेड किंगडम के ऊर्जा सुरक्षा और नेट जीरो विभाग (डीईएसएनजेड) के राज्य सचिव (एसओएस) द्वारा की गई, फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित की गई।

इस संवाद के तहत कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। यह सुझाव दिया गया कि संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) पर काम जारी रखा जाए, स्मार्ट मीटर शुरू किए जाएं, आउटेज प्रबंधन के लिए डिजिटलीकरण के माध्यम से ग्रिड उन्नयन किया जाए और आरडीएसएस के तहत नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और परिसंपत्ति निगरानी की जाए। ब्रिटेन-भारत सहयोग के तहत भारत में स्मार्ट विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने (एस्पायर) कार्यक्रम के तहत ब्रिटेन ने तमिलनाडु और गुजरात के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा निविदाओं के विकास, कुछ राज्यों के लिए हरित हाइड्रोजन नीतियों, ऊर्जा भंडारण के लिए 1 गीगावाट घंटे की निविदाओं के विकास के लिए ज्ञान साझा किया तथा भारत में सौर विनिर्माण को बढ़ाने के लिए इनपुट प्रदान किए।

(घ) : विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता पहलों में मोटे तौर पर उपकरणों के न्यूनतम ऊर्जा कार्यनिष्पादन मानकों में सुधार, वाणिज्यिक और आवासीय भवनों में ऊर्जा संरक्षण और स्थिर भवन कोड का कार्यान्वयन, उद्योगों में ऊर्जा संरक्षण उपायों में वृद्धि, परिवहन क्षेत्र में ईंधन अर्थव्यवस्था में सुधार शामिल हैं।

****